Haryana Vidhan Sabha

Debates

28th March, 1967

Vol. I – no.6

OFFICIAL REPORT

CONTENT5S

Tuesday, the 28th March, 1967

Pages

Starred Questions and Answers

Presentation of the Budget for the year 1967 – 68 and the(6)1

Vote- on –Account, 1967-68 (for three months, i. e., (6)4

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, the 28th March,1967

The Vidhan Sabha met in the hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Chandigarh- 1 at 11.00 A.M. of the clock. Mr. Deputy Speaker (Chaudhri Manphul Singh) in the chair.

Starred questions and answers

Export of cows and calves from the State

***12. Chaudhri Ram Lal**

(11) Shri Fateh Chand Vij : Will the Chief Minister be pleased to state whether the public . Relations Department, Haryana, has issued a poster staing that the Chief Minister of Haryana has done an act of historical impostance by imposing a legal ban on the export of cows and calves from the state; if so, the contents there of and the date since when the said ban has been imposed ?

Sardar Lachhman Singh (Transport Minister) : yes, a poster was issued. However, the Government's decision on the subject requires prior approval of the Government of India which has not so far been received.

श्री फतेह चन्द विज : क्या वजीर साहिब बतायेगे कि जब गवर्नमैंट आफॅ इडिया से मजूंरी नही आई थी तो यह पोंस्टर निकाल कैसे दिया ?

मंत्री : यह पिछी गवर्नमैंट का पोस्टर है। हो सकता हैं, इलैक्शन स्टंट हो।

चौधरी राम लाल : इस पोस्टर की बिना पर 19 जनवरी को स्वामी दयानन्द और मैंने कुछ गौंए रोकी थी, लेकिन वह घुड़ सवार पुलिस के जरिए दूसरे सूबे में पहुंचाई गई थी। क्या मैं जान सकता हूं िकइस की क्या वजह थी ?

Chief Minister : This has no relevancy with this question.

श्री मंगल सैन : यह जो करनराल में पोस्टर छपा था पण्डित भगवत दयाल का फोटो लगा कर जिसमें कुछ सिंद्धात की थोथी बातें लिखी हुई थी, वह क्योंकि सरासर झूठ थी इसलिए कया सरकार उनक` खिलाफ एक्शन लेने का विचार करेंगी?

मुख्य मंत्री : पोस्टर तो मैंने देखा नही कि उस में क्या लिखा है लेकिन वह डिसीजन लेने के लिए गवर्नमैंट आफ इंकिडया कीि ऐपरूवल लेनी जरूरी है जिसके लिए लिखा हुआ है लेकिन अभी तक मिली नही हैं।

Share of punjab Roadways Buses betw3een Punjab and Haryana State

***10. (1) Chaudhri Ram Lal**

(11) Shri Fateh Chand Vij : Will the Minister for Transport be pleased to state the number together with the models and makes of buses of the Punjab Roadways which fell to the share of unjab and Haryana, respectively, as a result of the reorganisation of the Punjab ?

Sardar Lachhman Singh : A statement is laid on the table ofr the house.

STABMENT

Make eidr esk up of buses which fell to the share of unjab and Haryana is as under :-

Serial No	Make	Punjab	Haryana
1	Dodge	89	297
2	Mercedez	319	14
3	Leyland	312	164
	Total	720	475

Models/ year – wise break up of buses of Haryana Roadways is as under:-

NUMBER AND MAKE

Put on route during year	Dodge	Mercedez	LEYLAND	TOTAL

1960 -61	38			38
1961-62	81		24	105
1962-63	97		2	99
1963-64	44		11	55
1964-65	8	12	51	71
1965-66	29		45	74
1966-67		2	31	33
TOTAL	297	14	164	475

As regards models of buses, which fell to the share of Punjab, the information is being ascertained from Punjab.

श्री फतेह चंद विज : इस सवाल के जवाब में बताया गया है कि हरियाण को 267 डाज ट्रक मिले और पंजाब के हिस्से सिर्फ 89 आए। क्या मैं जान सकता हूं कि यह रद्दी माल हरियाणा को क्यों ज्यादा दिया गया?

मन्त्री : उस वक्त हरियाणा के हकूक की हिफाजत सही ढंग से नही हुई इसलिए ऐसा हुआ था।

Agreement regarding Passenger Transport on 50:50 basis

***11(1) Chaudhri Ram lal**

(11) Shri Fateh Chand Vij : Will the Minister for Transport be pleased to state the time by which the agreement of 50:50 basis entered into by the Government with the Punjab Motor Union Regarding the Passengers Transport will expire together with the scheme, if any, proposed to be followed by the Government after the expiry of the said agreement ?

Sardar Lachhman Singh : (a)Agreement will expire on 30th june, 1960.

(b) As the new Governnment has taken over policy will be decided.

Shri Daya krishan ; I want to know whether the Government has taken over up to the extent of 50 per cent.

Minister : I would require a separate notice to answer this question.

Shri Daya Krishan : Sir, my supplementary arises out of the main question. My question is whether by this time the Goovernment has taken over 50 per cent of the buses.

Minister : Separate notice is required to answer it.

श्री दया कृष्ण : पैप्सू में सैंट परसैंट नैशनलाइजेशन का जो रूल है, क्या मौजूदा सरकार उस को फालो करेगी ?

Minister I We will decide the policy.

Shri Daya Krishan I It has already been decided. The question is whether the present government will follow that or not ?

Chief Minister: That will depend upon us.

Shri Daya Krishan : The house wants to know whether they will follow it or not.

Chief Minister : We will let you know after we have taken a decision. We can change your policies as well if we like.

श्री दया कृष्ण : क्या मुख्य मंत्री साहिब बताएंगे कि इस के मुताल्लिक वह कब तक गोर करेंगें?

Chife Minister : As soon as we can conyeniently find time. And that will depend upon you also.

Chaudhri Debi Singh : I wish to ask , through you, the Chief Minister whether he considers the policy of total nationalisation of bus servicers in Pepsu as bad ?

Chief Minister : The question does not arise. The Government took a decision. Now this Government is going to take certain decisions. We will let you know after we have decided whether we consider something good of bad.

Mr. Deputy Speaker : Question hour is over now.

PRESENTATION OF THE BUDGET FOR THE YEAR 1967-68 AND THE VOTEON ACCOUNT 1967-68 FOR THREE MONTHS 1.E. APRIL, MAY AND JUNE, 1967

Mr. Deputy Speaker: The Finance Minister will now present the Bidget for the year 1967-68 and the Vote –on-Account, 1967-68 (forthree months, i.e.m April, May and June, 1967).

भूमिका

1 वित मंत्री (श्री मूल चंद जैन) : श्रीमान् मैं व9र्ष 1967—68 का हरियाणा राज्य का वार्षिक वित विवरण पेश करने के लिए आपकीह सेवा में हाजिर हुआ हूं।

2 अगले वर्ष का बजट तैयार करते समय हमें हरियाणा के लोगों की जरूरतों तथा आकांक्षाओं का विस्तृत एवं समन्वित ढ।ग से जायज लेने औ।र उन्हें आर्थिक तौर पर व्यावहारिक रू‍प देने का प्रामि अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए हरियाणा के लोगों के लिए अगले वर्ष के बजट का विशेष महत्व हैं। इससे अब तक पिछड़े तथा कुछ हद तक उपेखित इस इलाके के विकास के लिए लोगों द्वारा बहुत देर से की जा रही निश्चायक प्रतिनिधित्व की मांग की पूर्ति होगी। यह अवसर और भी विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि सयुक्त दल को जोकि हरियाणा के लोगों की वास्वतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हैं जनता द्वारा इस में प्रदर्शित विश्वास को ठोस र्रू‍प देने का पहली बार मौका मिला है।

3 साधारणतया सरकार अपनी नीतियों तथा काय्रक्रमों का ब्यौरेवार प्रतिपादन करने के लिए इस अवसरी का लाभ उठाती परन्तु माननीय सदसय यह जानते हैं कि संयुक्त दल की सरकार ने अभी अभी कार्यभार संभाला है, इसलिए इसे पिछले कांग्रेस मंत्री –मंडल की हिदायतों के अनुसार तैयार किए गए बजट प्रस्तावों पर पूरी तरह नजरसानी करने का मौका नही मिला हैं ऐसा होने के कारण वर्तमान सरकार को बजट प्रस्तावों पर दोबारा विचार करने के लिए कुछ समय की र्जरूरत होगी ताकि इसके साधनों को लोगों के अधिकतम लाभ के लिए जितना जल्दी हो सके प्रयोग में लाया जा सके। चालू वित वर्ष कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए राज्य के प्रशासन को चलानें के लिऐ ऐसे समय तक जब तक हम बजट के आकड़ों पर पूरी तरह गौर नहीं कर लेते और सदन के सम्मुख नए प्रस्ताव पेश नही कर देते, आवष्यक खर्च करने के लिए विधान मंडल की मंजूरी लेना जरूरी है। अतः मैं वित वर्ष 1967–68 के पहले तीन महिनों के दौरान किए जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लेखा अनुदान प्राप्त करने की प्रार्थना करूंगा। चूंकि भारत के संविधानर के अनुच्छेद 202 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार विभिन्न मांगो के लिए मंजूरी प्राप्त करते समय वार्षिक वित विवरण को विधान मंडल के सम्मुख पेश करना ीाी जरूरी है, इसलिजए भूतपूर्व मंत्रि मंडल द्वारा तैयार किए गए वित विवरण की सदन के सामने पेश किया जा रहा है। नई सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक परिवर्तन बजट प्रस्तावों में किए जाएंगे और सदन के सामने उस समय

प्रस्तुत किए जाएगे जब यह वर्ष 1967–68 के बजट पर विस्तृत बहस के लिए बैठेगा।

आर्थिक स्थिति

4 राज्य को बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ समस्याऐ ंतो हरियाणा के विशष रू‍प से पिछड़े हुए होने तथा उसके पिछले कुछ वर्षो से तुलनपात्मक रूप से उपेक्षित रहने के कारण हैं और अन्य समस्याएं सारे देश की विकट आर्थिक स्थिति के कारण है। सदन को यह भली भांति विदित ही है कि नए पंजाब के क्षेत्रों की अपेक्षा हरियाणा सामाजिक आर्थिक विकास के लगभग सभी क्षेत्रों में पीछे है। कुदेक महत्वपूर्ण तथा निदर्शी तथ्यों का वर्णन यहां किया जाता है। जबकि दानों रपाज्यों में कृषि अधीन क्षेत्र लगभग बराबर हैं, हरियाणा में नकदी फसले के अधीन क्षेत्र केवल 12 लाख एकड़ हैं ओर इसके मुकाबले में नए पंजाब में यह 20 लाख एकड़ हैं । हरियाणा में 75 प्रतिशत क्षेत्र में कम उत्पादन वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, और चने आदि की ही खेत5ी की जाती है, जबकि पंजाब में ऐसी फसलों के अधीन केवल 25 प्रतिशत द्वोत्र आता है। कुछ क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र केवल 31.2 प्रतिशत है जबकि नए पंजाब में यह 62.7 प्रतिशत है। हरियाणा में रासायनिक खाद की खपत भूतपूर्व पंजाब राज्य की कुल खपत की लगभग 1/4 भाग है। हरियाणा बड़े पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में तो कुछ अच्छी स्थिति में है परन्प्तु छोटे पैमाने के उद्योगौं का जिनके लिए भुतपूर्व

पंजाब इतना प्रसिद्ध था, 75 प्रतिशत नए पंजाब में चला गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जब कि पंजाब में साक्षरता 26.7 प्रतिशत है, हरियाणा में यह केवल 19.8 प्रतिशत है। नारी शिक्षा की स्थिति विशेशतया निराशाजनक है, जिसमें साक्षरता की प्रतिशतता नए पंजाब से लगभग आधी हैं सम्पूर्ण स्थिति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1964–65 में मूल्यों के नियतांक के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय केवल 362 रूप्ये थी जबकि नए पंजाब में यह 430 रूप्ए थी।

5 उपरलिखित आंकड़ों से भी राज्य की न्यूनताओं की पूरी जानकारी नही मिलती। संयुक्त पंजाब की भुतपूर्व सरकार क्षरा लेनदारियों और देनदारियों के विभाजन के लिए नियुक्त समिति के अनुमकानों के अनुसार वर्ष 1966 –67 में पंजाब का अनुमान 41 करोड़ रूप्ए लेया`गयाथा जबकि हरियाणा की जनसंख्या ीाी पंजाब की जनसंख्या का केवल दो तिहाई ीाग है। जहांतक केवल कर से प्राप्तियों का प्रश्न है समिति का यह अनुमान था कि पंजाब से होने वाली आय 18.82 करोड़ रूपथी। यह समिति इस निष्कर्ष पर भी पहुंची कि हरियाणा में चालू योजना से बाहर के राजस्व बजट से बकाया रकम केवल 3.64 करोड़ रूप्ए होगी जबकि पंजाब में ऐसी बकाया रकम 17.68 करोड़ रूप्ए होगी। इस तरह हमारे साधन हमारे पड़ोसी राज्य की तुलना में बहुत सीमित हैं और विमकास के अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयत्न करना है।

मुख्य प्राथमिकताएं

6 सरकार को इन कठिनाइयों का पूर्ण ज्ञान है। सरकार ने अपने साधनो के अन्दर रहते हुए अबतक पिछड़े नए इस इलाके के विकास तथा समाज के निर्धन वर्गों की उन्नति के लिए पूरी पूरी कोशिश करने का पक्का इरादा कर रखा है। राजय ने भारी मुश्कलों के बावजूद कृषि विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वस्तुतः यह हरियाणा के मेहनती काश्तकार के कठिन परिश्रम का ही फल है। उसने अपने तुच्छ साधनों से अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने की हर संभव कोशिश की है। नइर्द सरकार की यह कोशिश रहेगी क थोड़े से थोड़े समय में उसे और खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक साधन जुटाए जांए । सरकार कृषि उत्पादउन बढाने के लिए पूरा जोर लगाएगी । इस प्रयोजन के लिए रासायनिक खाद,बीज, औजार और कीटनाशी दवाइयों आदि चीजें मुहैया की जांएगी। छोटी सिंचाई तथा ट्यूबवैलों को बिजली देने पर विषेश बल दिया जाएग। जिला महेंन्द्रगढ, जिला गुडगांव विशेषकर तहसील रेवाड़ी और जिला रोहतक की झज्जर तहसील के खुश्क इलाकों में पानी ले जाया जाएगा । तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा और सूखाग्रस्त तथा अकाल पीड़ीत क्षेत्रों में पानी की सप्लाई का प्रबन्ध किया जाएगा। हरिजनों और अनुसूचित जातियों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ऐसा ही प्रयास औद्योगिक क्षेत्र में भी किा जाएगा और दिल्ली की निकटता का पूर्ण लाभ उइाया जाएगा। इन क्षेत्रोंकी उन्नति के लिए वितीय साधन जुटाने के लिए हर संभव यत्न करना बडा जरूरी है। साथ ही नई सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि प्राप्त निधियों से यथासंभव पूरा फायदा उठाया जाए। ऐसा केवल तभी संभव हो सकता है यदि लोगों को सव्चद तथा कुशल प्रशासन मिले और भ्रष्टाचार को सभी स्तरों पर खत्म किया जाए। संयुक्रैत दल की सरकार के काय्रक्रम में इस बात को सबसे अधिक महत्व दिया गया है । सरकार क्षरा प्रशासनिक खच्र में तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के निष्पादन में ज्यादा से ज्यादा बचत करने कीह कोशिश की जाएगी।

बजट तैयार करने में कठिनाइयां

7 इससे पहले कि मैं सदन के समक्ष वर्ष 1967 –68 के लिए राज्य की वितीय स्थिति का वर्णन करूं, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कुछ कठिनाईयों की ओर दिलाता हूं जो किस वर्ष के बजट प्रस्तावों को तैयार करने में सामने आई है। आने वाले वर्ष के प्रस्तावों को तैयार करते समय पुरानी प्रवृतियों का ध्यान रखना बडा जरूरी होता है। चूंकि हमारे राजय को अस्तित्व में आए केवल पांच ही महीने हुए हैं इसलिए पुरानी प्रवृतियों के साथ कोई महत्वपूर्ण तुलना संभव न होने से इसे सामान्य रू‍प में ही लिया गया है। बजट सम्बंधी कियाविधि में भी कुछ परिवर्तन आए है। इससे पहले भारत सरकार से विभागीय आंकड़ों के आधार पर

सहायता प्राप्त की जाती ीी। अब उन्होंने केवल लेखा परीक्षा किए गए आंकड़ों के आधार पर ही सहाचयता देने का फैसला किया हैं इस कारण योजना बजट और सामान्य बजट को अलग –2 तैयार किया गया हैं राजय बिजली बोर्ड की लेनदारियों तथा देनदारियों के बारे में भी कुछ कठिनाइयों सामने आई। भाखड़ा नंगल तथा बयास प्रायोजनाओ और कुछ अन्य निगमों तथा संस्थाओं के कारण अभी बाकी हैं। इनक ` बारे मे आमदनी तथा खर्च के अनुमानों को कुछेक पूर्वानुमानों तथा अस्थायी नियतनों के आधार र तैयार किया गया हैं, जिसका ब्यौरा वित सचिव के ज्ञापन में दिया गया है। अगर बाद में कोई परिवत्रन करना आवश्यक हुआ तो दोहराए गए अनुामन पेश करते समय इन की सूचना सदन को दे दी जाएगी।

वितीय स्थिति

वर्ष 1966–67 और 1967–68 के लिए प्राधिकृत खर्च

8 वर्ष 1966–67 और 1967–68 की वितीय स्थिति के संबध में ब्यौरे वार सूचना के लिए माननीय सदस्यों का ध्यान वित सचिव के बजट ज्ञापनन की ओर दिलाया जाता है। यहां संक्षेप रू‍प में ही स्थिति पर प्रकाश डालना प्रयाप्त होगा।

9 जैसे कि सदन को पता ही हैं, 1 नवंबर, 1966 से 31 मार्च, 1967 की अवधि के दौरान खर्च की मंजुरी राज्यपाल से ले ली गई थी। प्राधिकृत राशि 8,567लाख रूपए थी (मतदत 52,98

लाख रूप्ए तथा प्रभारित 3,296 लाख रूपए) बाद में कुछ विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 292 लाख रूप्ए (मतदत 259 लाख रूप्ए और प्रभारित 33 लाख रूपए) की अतिरिक्त मंजूरी ली गई। इसलिए 1 नंवबर, 1966 से 31 मार्च, 1967 की अवधि के लिए खच्र के वास्त `प्राधिकृत कुल रकम 88,59 लाख रूप्ए थी (मतदत 55,57 लाख रूप्ए और प्रभारित 33,02 रूपए) इसमें से प्राधिकृत कुल निवल खच्र 69,81 लाख रूप्ए हुआ (मतदत 36,80 लाख रूप्ए और प्रभारित 33,01 लाख रूपए)।

वर्ष 1966–67 के दोहराए गए अनुमान

10 राज्य पाल द्वारा प्राधिकृत इस व्यय के प्रति विभागों को 1966–67 के लिए अपने संशोधित अनुमान देने को कहा गया। सम्भाव्य प्राप्तियों के अनुमान भी प्राप्त हो गए है। विभिन्न लेने `देन को हिसाब के बाद समुची स्थिति इस प्रकार है –

(रूपए लाखों में)

1	**अथ शेष (ओपनिंग बैलेस)**	
	1 लेखा पुस्तकों के अनुसार	**–1,07**
	2 प्रतिभूतियां में लगाया गया धन	**1,92**
2	**राजस्व लेखा :**	
	1 प्राप्तियां	**25,36**

	2 व्यय	21,77
	ब्चत (+) घाटा (–)	+3,59
3	पूजीगत लेखा	–3,62
4	सरकारी कर्जे :	
	लिया गया कर्ज	12,30
	वापसी अदायगियां	10,49
		+1,81
	कर्जे तथा पेंशगियां :	7,80
	पेशगियां	2,67
	वसूलीयां	2,67
	निवल	5,13
6	फुटकर निधि	+75
7	अनिकि कर्जा	+22
8	जमा तथा पेशगियां	+34
9	प्रषण (निवल)	+8
10	इतिहेस	

1 लेखा पुस्तकों के अनुसार	**—303**
2 लगाया गया धन	
क खजाना बिलों में	
ख प्रतिभुतियेां में	**1,92**

11. पहली नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य का अथ शेष 107 लाख रूप्ए घाटे का था। भुत पूर्व पंजाब राज्य की प्रतिभूमियों में से उतराधिकारी राज्यों के बीच अभाी तक 558 लाख रूप्ए की प्रतिभुतियां बांटी गई है जिसमें से हरियाणा को 1,92 लाख रूप्ए का हिस्सा मिला है। अभी लगभग 846 लाख रूप्ए की प्रतिभुतियां उतराधिकारी रराज्यसों के बीच बांटी जानी बाकी है।

12 वर्ष 1966—67 के 5 महीनों के दौरान विभिन्न शीर्षो के अधीन हुए लेन देन को देखते हुए यह सम्भावना की जाती है कि इस वर्ष के अन्त में 303 लाख रूप्ए का घाटा शेष रह जाएगा।

व्र्ष 1967—68 के अनुमान

13 1967–68 वर्ष के बजट प्रस्तावों के बारे में यह अंदाजा लगायाजाता है कि वर्ष के अन्त में निम्नलिखत लेन देनप के परिणामस्वरूप 865 लाख रूप्ए का घाटा होगा :–

(रूपए लाखों में)

1.	अथ शेष :	
	1 लेखा पुसतको के अनुसार	–3,03
	2 प्रतिभूतियों में लगाया गया धन	1,92
2	राजस्व लेखे में प्राप्तियां	56,04
	खर्च	58,70
	(घाटा) (–)	–2,66
3.	पूंजी गत खर्चा (निवल)	–8,56
	(सिंचाई लोक निर्माण विभाग)	
4.	कर्जे तथा पेशगियां :	
	पेषगियां	18,38
	वसूलियां	7,29
	निवल	–11,09

5. सरकारी कर्जा :

लिया गया कर्जा	53,36
वापसी अदायगी	41,90
निवल	+11,46

6. अनिधिक (अनफंडिड) कर्जा (निवल)	+57
7. जमा तथा पेशगियां (निवल) (विभाग)	+4,47
8. प्रेषण (निवल)	+19

9. इतिशेंष (कलोजिंग बैलेंस)

1 लेखा पुस्तकों के अनुसार	78,65
2 प्रतिभूतियों में लगाया गया धन	1,92

14. माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि 58,70 लाा रू0 के अनुमानित राजस्व खर्चे के मुकाबले में राजस्व प्राप्तियां 56,04 लाख रू0 है। इससे राजस्व घाटा 266 लाख रू0 दिखाई देता है। यह उललेख कर दिया जाए, कि 5870 लाख रू0 के कुल राजंस्व खर्चे में से 48,16 लाख रू0 योजना से बाहर का खर्च है जबकि 10,54 लाखरू0 की बाकी राशी योजना का खर्च पूरा करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों के लिए रखी गई है। कुल पूंजीगत खर्चा 856 लाख रू0 निकलता है।

यह खच्र अधिकांश औद्योगिक तथा आर्थिक विकास (167 लाख रूपये), बहुमु,खी नदी घाटी प्राजेक्ओं तथा सिंचाई स्कीमों (494 लाख रू0) लोक निर्माण (169 लाख रू0) और परिवहन सेवा (31 लाख रू0) पर ही होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है इन आंकंड़ों की फिर से जांच की जाएगी और ऐसो परिवत्रन करने के बाद, जो आवश्यक समझे जांएगे प्रस्ताव सदन में पेश कर दिए जाएंगें।

राज्य की चौथी पंच वर्षीय योजना

15. इस समय संक्षेप चौथी पंचवर्षीय योजना तथा 1967–68 की वार्षिक योजना के वितीय साधनों पर प्रकाश डालना उचित होगा। कुछ समय पहले योजना कमीशन ने हरियाणा की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 174.4 करोड़ रूपए की रकम नियत की थी। इसमें 6 करोड. रूप्ए को वह रकम भी शामिल है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए गए कुछेक कार्यक्रमों के साथ केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को हस्तान्तरित की जाएगी। इस योजना काय्रक्रम को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य को 77 करोड़ ⁄ रूप्ए तक के साधन लजुटाने होंगे तथा बाकी रकम अर्थात 97.4 करोड़ रूपएकेन्द्र सरकार द्वारा योजना बनुदान के रू॰ में दिए जाएें।

वर्ष 1967–68 की वार्षिक योजना

16 वर्ष 1967—68 की वार्षिक योजना के आकार के सम्बधं में योजना कमीशन के साथ अभी तक अंतिम रू᠑ से कोई निर्णय नही हुआ है। अगले वर्ष में प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता का निश्चित संकेत मिलते ही इस बात का निर्णय कर दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार की ओर से इस प्रकार का निश्चित संकेत दिया जाना इस बात पर निभ्रर करेगा कि कें न्द्र सरकार के सामने अपने साधनों की तस्वीर अधिक साफ हों, जिवसमें साधनों का अधिक जुटाना और वर्ष 1967'—68 के लिए अस्थायी रू᠑ से योजना के खर्च की रारशि 27.93 करोड. रू᠑ए निर्धारित की िि जोकि राजय की पंजवर्षीय योजना का मोटे तौर पर 17 प्रतिशत भाग है। इसकी तुलना में योजना कमीशन ने अभी तक केवल 13.50 करोड.रू᠑ए की सहायता देने का वचन दिया हैं जोकि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवि के साधनों के 14 प्रतिशत भाग से कुछ ही अधिक है। कमीशन ने स्वयं इस बात का संकेत किया है कि ये आंकड़े अस्थायी है। और मै सदन को विश्वास दिलाता हूं कि केद्रीय सहायता की मात्रा को बढवाने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाएगा ताकि योजना के साधनों में होने वालें घाटे को काफी हद तक पूरा किया जा सकें।

17. इस तथ्य पर तथा अन्य अनिश्चित बातों पर ध्यान देते हुए इस समय इस बात का अनुमान लगाना संभव नही है कि अमें कितने वितीय सांधन जुटाने की जरूरत पड़ेगी। इसके इलावा जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं नई सरकार की अभी तक समय

नहीं मिल सका है कि काम से जुझती । सरकार प्रशासनिक काग्रक्षमता पर बुरा प्रभाव डाले बिना अधिक से अधिक बचत करने के लिए वचनबद्ध है ताकि इस घाटे को कम किया जा सके। इस घाटे के कुछ भाग को राज्य उत्पाद कर से प्रत्याशित अधिक आय से पूरा किया जा सकता है। इस लिए सरकार का यह सुझाव है कि इस घाटे को कुछ देर के लिए ज्यों का तयों रहने दिया जाए। इस सम्बधां में निकट भविष्य में ही सरकार अपने प्रस्ताव पेश करेंगी।

कर व्यवस्था में सुधार

18. मैं यहां इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि यद्यपि पहले भी सामान्य बिक्री कर और केंद्रीय बिक्री कर संबंधी अपीलों की सुनवाई करने और उनका निर्णय करने के लिए एक ट्रिब्यूनल सीापित करने की ‘घोषणा की गई है यह सरकार इस बारे में शघ्र ही कार्यवाही करेगी और व्यापारियों का विश्वास बनाए रखने के प्रयोजन से इस निर्णय को लागू करने के लिए जल्दी ही कानून बनाएगी। उतरी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में विक्री कर की दर में अधिक से अधिक एकरूपता लाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। इसके अलावा कर की चोरी को रोकने और करो केअलावा अन्य प्राप्तियों को अधिक से अधिक बढाने के एि कड़े कदम उठाए जाने का भी प्रसताव है।

स्रकार गृह कर तथा सम्पति कर की व्यवस्था में सुधार करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। 8प्रंशसा)। इस समय राज्य सरकार शहरी अचल सम्पति पर मरम्मत और कुछ अन्य कटौतियों के लिए 10 प्रतिशत छूट देने के बाद सम्पति के कुछ वार्षिक मूल्य पर 10 प्रतिशत के दर से कर वसूल कर रही हैं साथ ही नगरपालिकाएं भी । इस प्रकार शहरी सम्पतियों पर दो निकायों द्वारा कर वसूल किया जा रहा है। इसलिए एक ही प्रकार के काम के लिए दो ऐजैसियां बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती हैं और परिणामस्वरूप उन द्वारा किए गए निध्र्धारणों में भी विभिन्नता आ जाती है। अब सरकार एक ही एजेंसी द्वारा दानों करों के निर्धारण तथा वसूली और उन में से स्ाानीय निकायों को कुछ भाग देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं इससे वसूलियों पर होने वाला खर्च भी कम हो जाएगा और टैक्स की चोरी की भी रोकथाम हो जाएगी।

करों से राहत

19. नई सरकार किसानों तथा समाज के अन्य निर्धन वर्गों को करों से राहत देने पर विचार कर रही है।जबकि अभी इस प्रश्न पर विभिन्न पहलुओं से विचार करना हैं, यह सुझाव है कि पांच एकड. तक के क्षेत्र की जोत को भू–राजस्व से एकदम छूट दे दी जाए । माननीय सदस्यों को यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि संयुक्त दल सरकार यह प्रस्ताव करती है कि पिछले बन्दोबस्त के बाद कुओं द्वारा सिचाई के अधीन लाई गई बारानी भूमि पर विशष

चाही दरों से लगाए जा सकने वाले भूराजस्व को खत्म कर दिया जाए।

सरकारी कर्मचारियों को रियायतें

20. सरकार बढ़ती हुई कीमतों के कारण अपने कम्रचारियों की हालत के बारेमें पूरी तरह से सचेत है और अनुभव करती है कि इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठारए जाने चाहिएं। सरकार को यह भी मालूम है कि कई रारज्यों सेवाओं द्वारा अपने अपने वेतनमान बढ़ाए जाने के लिए लगातार मांग की जाती रही है। कॉलेज और स्कूल अध्यापकों के वेतन मान बढाने के प्रश्न पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन) और कोठारी कमीशन द्वारा की गई सिफारशों पर सरकार पहले ही विचार कर रही हैं इसी तरह कुद दुसरी सेवाओं की समुचित मोगों पर भीा विचार करना हैं इस पर शीघ्रता से और विस्तारपूर्वक तथा समन्वित ढंग से विचार किया जाना चाहिए । इस कठिछन और जटिल समस्या पर पूरी तरह जांच किए जाने तक मेरे लिए इस समय दइस बारे में कुछ अधिक कहना सीाव या उचित नहीं होगा। फिर भी यह स्पष्ट है कि इस मामले में आंशिक यप से निर्ण्या य करना और कर्मचारियों की किसी विशेष श्रेणी के वेतन मानों का दूसरी सेवाओं पर इस से पड़ने वाले प्रीााव को ध्यान में लिए बिना अलग से दाहराना कठिन और हानिकर होगा। इसलिए यह सुझाव है कि पहली सरकार द्वारा उक्ख स्तरीय वेतन कमेटी बनाने के निर्णय पर पाबंद रहा जाए। यह कमेटी एक विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र

देगी । सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक करोड़ रूप्ये का कर्जा देने का भी फेसला किया है। ताकि वे बाजार में गेहू आने के समय इसे खरीद सके। यह पेशगी उनसे उसी वर्ष में आसान किस्तों में वसूल कर ली जाएगी। इस कर्जे पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर अनाज की बढती चढती कीमतों का असर काफी हद तक कम हो जाएगा।

आभार प्रदर्शन

21. भाषण खत्म करने से पहले, मै। कमिश्नर योजना तथा वित और उनके सुयोगय अधिकारियों तथा अमले को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इन विस्तृतन बजट प्रस्तावों को बड़ी मेहनत से तैयार किया हैं, हांलाकि ये विभाग अभी तक पूरी तरह संगठित नही हो जाये थे। मैं, महालेखापाल पंजाब तथा हरियाणा द्वारा दी गई सहायता के लिए भी आभारी हूं। मैं चडीगढ़ प्रशासन का भी आभारी हूं कि उन्होंने बजळट को समय पर छपवाने के लिए हमें सहयोग दिया। श्रीमान्, अब मैं आपकी इजाजत से 1967–68 के बजट अनुमान पेश करता हूं ।

जय हिन्द

श्री मंगल सैन : औन ए प्वांयट आफ आडर्र, सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चौधरी रिजक राम कांग्रेस छोड़कर

हमारे संयुक्त दल में आ गए है। after crossing the floor of the House ?(इस समय चौधरी रिजक राम चौधरी सिरी चन्द्र की सीट पर बैठे उन से बातें कर रहे थे।

Mr. Deputy Speaker : This is no point of order.

चौधरी रिजक राम : यह उधर जाने की सोच रहे हैं।(हंसी)

चौधरी सिरी चन्द :आए गए समझो।(हंसी)

श्री उपापध्यक्ष : कल दस बजे तक के लिए इस हाउस की बैठक स्थगित की जाती हैं।

The sabha then adjourned till 10.00 a.m. on weduesday the 29th 11.35 A.M. Marxh, 1967.